की पहचान की गई हैं। रेलों और महाराष्ट्र सरकार के एक अध्ययन दल द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन में 200 करोड़ रूपए के शुद्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया हैं जिसका रेल से संबंधित परियोजना में उपयोग किया जाएगा। बहरहाल, गत दो वर्षो के दौरान मुम्बई में स्थावर सम्पदा से आमदनी में भारी गिरावट आई हैं।

रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जे से राजस्व हानि

2088. **श्री ईश दत्त यादव** :
श्री रामगोपाल यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया गया हैं और उस पर निर्माण हुआ पड़ा हैं तथा कई जगहों पर निर्माण कार्य अभी भी जारी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया हैं और इसे कब से और किस-किस के द्वारा कब्जाया गया हैं;

(ग) अनधिकृत रूप से कब्जाई गई भूमि से अनधिकृत रूप से कब्जा किए जाने की तारीख से आज तक रेलवे को राजस्व की कितनी हानि हुई हैं; और

(घ) सरकार रेलवे की अनधिकृत रूप से कब्जाई गई भूमि को कब तक और किस प्रकार मुक्त कराएगी?

रेल मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) लगभग 2457 हेक्टेयर खाली पड़ी रेलवे भूमि पर लगभग 1.62 लाख अतिक्रमणकारियों का अनधिकृत रूप से कब्जा हैं। ये अतिक्रमण समय-समय पर हुए हैं। यद्यपि फील्ड में अधीनस्थ रेल कर्मचारी ऐसे अतिक्रमणों का ब्यौरा तैयार करने का काम में लगे होते है, फिर भी अतिग्रमणकारियों के नामों की प्रमाणिकता की पुष्टि करना हमेशा संभव नहीं हैं क्योंकि अतिक्रमण करने वाले शिफ्ट होते रहते हैं। यदि यह विपुल सूचना तैयार करने का प्रयास भी किया जाता हैं तो यह अप्रमाणित ही होगी।

(ग) रेलवे की खाली पड़ी भूमि रेलवे की भविष्य में विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित हैं। इस प्रकार कोई राजस्व हानि नहीं हुई हैं।

(घ) अतिक्रमणों को हटाना एक सत्त प्रक्रिया हैं और खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती हैं।

Third railway line between Virar and Ahmedabad

2089. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) wheter it is a fact that the Western Railway has recommended a third railway line between Virar and Ahmedabad;

(b) whether Government will react to the proposal favourably, and sanction the project keeping in view the fact that Gujarat is a fast developing State and to cope up with its infrastructual requirements and increase in volume of traffic it will be necessary; and

(c) whether it is a fact that the feasibility report of the railways has certified it to be a viable and economically profitable project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, PARLIAMENTARY AFFAIRS AND PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) Yes, Sir. The justification for the line has been accepted. Further necessary action has been initiated for obtaining the requisite clearances so that the project can be included in the next year's budget.

Commission/royalty on the supply of newspapers in Rajdhani/Shatabdi Express trains

2090. SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have fixed a percentage of commission/royalty to be recovered from the book stall Contractors on the supply of newspapers in the Shatabdi and Rajdhani Express Trains uniformly;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is a fact that newspapers are being supplied in all Shatabdi and Rajdhani Express Trains in all the Zonal Railways; and

(d) if so, the names of newspapers which are being supplied in each of these trains?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, PARLIAMENTARY AFFAIRS AND PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) Yes. Sir.

(b) Commission charges are fixed at the rate of 15% of the cost of newspaper or 50% of the commission received by the newspaper agent whichever is higher.

(c) Yes, Sir.

(d) A Statement is attached.